



Daily

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

11 February



Quote of the Day

UPSC



SSC

आपकी सोच आपकी सीमाओं को
निर्धारित करती है,
इसलिए अपनी सोच को अनचाहे
सीमाओं से मुक्त करें।

- स्वामी विवेकानन्द

100% East Policy → অসম পূর্বত্ব ২০২৫

↓
বিদেশী দ্বি

অসম মৈ হোণা দুনিয়া কা সবসে বড়া झुमुर नृत्य महोत्सव

UPSC Syllabus Relavanace

- **UPSC Mains Paper 1**





- ▶ असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमुर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार है।
- ▶ यह आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा।
- ▶ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि इस ऐतिहासिक अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे।





- ▶ असम इस कार्यक्रम में 7,500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
- ▶ यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ-साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा।



मुख्य विशेषताएँ

आयोजन का विवरण

- ▶ तारीख: 24 फरवरी 2025
- ▶ अवसर: एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन (25-26 फरवरी) से पूर्व
- ▶ स्थान: गुवाहाटी, असम
- ▶ मुख्य अतिथि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



मुख्य विशेषताएँ

झूमुर नृत्य प्रदर्शन

- ▶ यह अब तक का सबसे बड़ा झूमुर (झूमइर) नृत्य प्रदर्शन होगा।
- ▶ इसमें 7,500 से अधिक नर्तक भाग लेंगे। ✓
- ▶ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ✓✓



मुख्य विशेषताएँ

निवेश शिखर सम्मेलन – एडवांटेज असम 2.0

- ▶ पहली बार 2018 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
- ▶ मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश पर केंद्रित।
- ▶ राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद।



मुख्य विशेषताएँ

आयोजन की तैयारियाँ

- ▶ नृत्यकारों के लिए मास्टर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं।
- ▶ विधानसभा और जिला स्तर पर अभ्यास सत्र कराए जा रहे हैं।
- ▶ गुवाहाटी में अंतिम पूर्वाभ्यास आयोजित होगा ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

कार्यक्रम
4 मई



मुख्य विशेषताएँ

असम की प्रगति और निवेश संभावनाएँ

- ▶ असम पहले ही सबसे बड़े बिहू प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है।
- ▶ मुख्यमंत्री ने अपराध दर में गिरावट और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल की सराहना की।



मुख्य विशेषताएँ

असम की प्रगति और निवेश संभावनाएँ

- ▶ व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।
- ▶ बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी से प्रगति हो रही है।



निष्कर्ष

- ▶ असम का यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

झूमर नृत्य



झूमर नृत्य

- झूमर नृत्य, भारत के कई राज्यों में किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह नृत्य, पंजाब में भी किया जाता है। झूमर नृत्य के कई प्रकार हैं, जैसे कि जननी झूमर, मर्दाना झूमर, और हरियाणवी गिद्धा।



झूमर नृत्य के बारे में:

- झूमर नृत्य, भारत के इन राज्यों में किया जाता है - झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, और पश्चिम बंगाल.
- झूमर नृत्य, पाकिस्तान के पंजाब में भी किया जाता है.
- झूमर नृत्य, भावनात्मक गीतों पर किया जाता है.
- झूमर नृत्य, मुख्य रूप से फसल के मौसम में किया जाता है.



झूमर नृत्य के बारे में:

- झूमर नृत्य, शादी समारोहों में भी किया जाता है.
- झूमर नृत्य, कुड़मी महतो, कुम्हार, उरांव, और मुंडा समुदाय के लोग करते हैं.
- झूमर नृत्य, महिला प्रधान नृत्य भी है.
- झूमर नृत्य, मगध और आस-पास के ज़िलों में वसंत का स्वागत करने के लिए किया जाता है.



CURRENT AFFAIRS QUIZ

असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव आयोजित करेगा।
इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह महोत्सव 'एडवांटेज असम 2.0' निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा।
2. इस महोत्सव का उद्देश्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
3. यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया जाएगा।

उपयुक्त विकल्प चुनें:

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं।
- (C) केवल 1 और 3 सही हैं।
- (D) सभी कथन सही हैं।



राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग - चर्चा में

UPSC Syllabus Relevanace

- **UPSC Mains Paper 2**



सत्यमेव जयते

NATIONAL COMMISSION FOR
SAFAI KARAMCHARIS

ONLINESS IS NEXT TO GOD



- ▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31.03.2025 से आगे तीन वर्षों के लिए (अर्थात् 31.03.2028 तक) बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।

NCSK



„CLEANLINESS IS NEXT TO GODLINESS.“

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग



- ▶ एनसीएसके के तीन वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपये का होगा।
- ▶ इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई कार्य करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।



आयोग के कार्य

एनसीएसके से जुड़े कार्य इस प्रकार हैं:

- ▶ क) सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
- ▶ ख) सफाई कर्मचारियों और विशेष रूप से मैला ढोने वालों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना।



आयोग के कार्य

एनसीएसके से जुड़े कार्य इस प्रकार हैं:

- ▶ ग) विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और:
 - ▶ (i) सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रमों या योजनाओं,
 - ▶ (ii) सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को कम करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों, दिशा-निर्देशों आदि के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना,
 - ▶ (iii) सफाई कर्मचारियों आदि के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उपाय।



आयोग के कार्य

एनसीएसके से जुड़े कार्य इस प्रकार हैं:

- ▶ घ) सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और वेतन से संबंधित कार्य स्थितियों का अध्ययन और निगरानी करना।
- ▶ ड) सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, जिसमें सफाई कर्मचारियों के सामने आ रही किसी भी मुश्किल या अक्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।
- ▶ च) कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा जा सकता है।



आयोग के कार्य

मैला उठाने वालों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम 2013) के प्रावधानों के तहत, **एनसीएसके निम्नलिखित कार्य करेगा:**

- ▶ i. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना। ✓
- ▶ ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना तथा आगे कदम उठाए जाने के लिए आवश्यक सिफारिशों के साथ अपने निष्कर्षों को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना।



आयोग के कार्य

मैला उठाने वालों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम 2013) के प्रावधानों के तहत, **एनसीएसके निम्नलिखित कार्य करेगा:**

- ▶ iii. इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना।
- ▶ iv. इस अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामले का स्वतः संज्ञान लेना।



पृष्ठभूमि:

- ▶ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 को सितंबर, 1993 में अधिनियमित किया गया था।
- ▶ एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त, 1994 में किया गया था।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आयोग सफाई कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु सिफारिशें करता है।
2. यह आयोग स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) है, जिसका गठन 2013 में हुआ था।
3. मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी इसका प्रमुख कार्य है।

सही उत्तर का चयन करें:

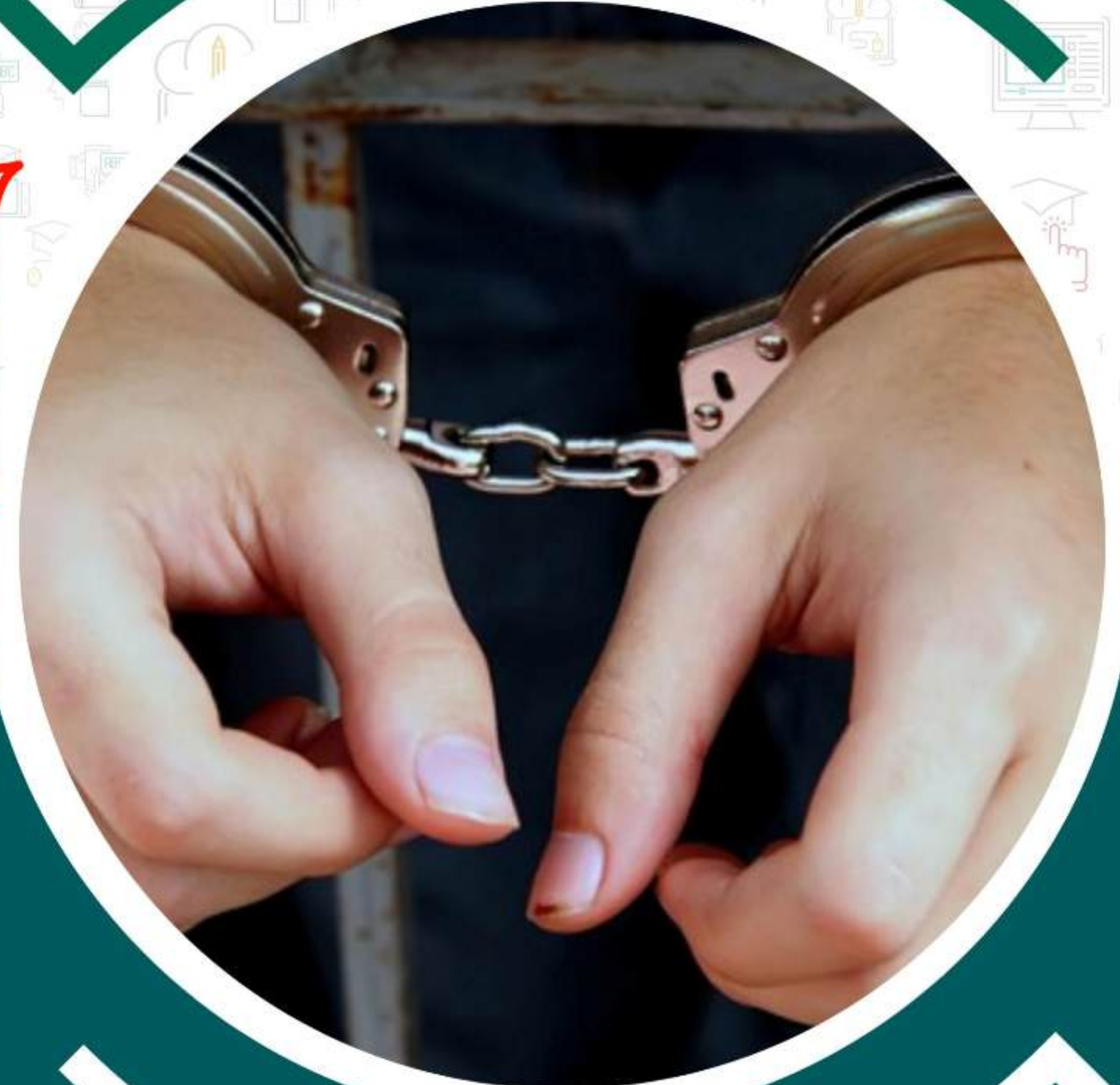
- (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
- (B) केवल 1 और 3 सही हैं। ✓✓
- (C) केवल 2 और 3 सही हैं।
- (D) सभी कथन सही हैं।



गिरफ्तारी के आधार पर जानकारी ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

UPSC Syllabus Relavanace

- **UPSC Mains Paper 3**





गिरफ्तारी के आधार पर जानकारी ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- ▶ सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने की आवश्यकता एक "औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है"।





- ▶ सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला विहान कुमार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया।
- ▶ उच्च न्यायालय ने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली और सीसीटीवी फुटेज मांगने वाली उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया था।



गिरफ्तारी के आधार पर जानकारी ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- ▶ सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अस्पताल में आरोपी को जंजीरो और हथकड़ी से बांधने पर कड़ी असहमति व्यक्त की।
- ▶ यह कदम अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

गिरफ्तारी
वकील



फैसले के प्रमुख बिन्दु

- ▶ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए।
- ▶ गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी न देने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।



फैसले के प्रमुख बिन्दु

- ▶ न्यायालय ने जोर दिया कि अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकारों (संविधान के भाग III) का हिस्सा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- ▶ यदि गिरफ्तारी के आधार शीघ्रता से नहीं बताए जाते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।



फैसले के प्रमुख बिन्दु

- ▶ गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदारों या नामित व्यक्तियों को भी सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे वकील की मदद लेना, के माध्यम से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।
- ▶ न्यायालय ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना देना एक आदर्श प्रथा है।



निर्णय के प्रभाव

जांच और परीक्षण पर प्रभाव:

- ▶ न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का पालन न करने से जांच, आरोप पत्र या परीक्षण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, भले ही गिरफ्तारी को अवैध माना गया हो।
- ▶ गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन यदि अलग से संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं तो जांच या मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है।



निर्णय के प्रभाव

अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन पर न्यायालय का कर्तव्य:

- ▶ यदि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय को गिरफ्तार व्यक्ति की तुरंत रिहाई का आदेश देना चाहिए, भले ही जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध लागू हों।
- ▶ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन प्राथमिकता है, तथा प्रतिबंधों के बावजूद जमानत प्रदान की जा सकती है।



निर्णय के प्रभाव

जांच अधिकारी पर सबूत का भार:

- ▶ अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन को साबित करने का भार जांच अधिकारी/एजेंसी पर है।
- ▶ यदि गिरफ्तार व्यक्ति गैर-अनुपालन का आरोप लगाता है, तो पुलिस को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि आधारों की जानकारी उचित रूप से दी गई थी।



महत्व

- ▶ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 22(1) के महत्व पर बल मिलता है कि गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया के अनुसार की जाए।





महत्व

- ▶ न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने तथा अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए इस प्रावधान का अनुपालन आवश्यक है।



अनुच्छेद 22

- ▶ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद, उसे तुरंत गिरफ्तारी के कारण बताने चाहिए. साथ ही, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार भी मिलना चाहिए. यह अनुच्छेद, गैरकानूनी और लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकता है.



अनुच्छेद 22

- ▶ गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना ज़रूरी है.
- ▶ गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है.
- ▶ गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए.



अनुच्छेद 22

- ▶ निवारक निरोध के मामलों में, अधिकारियों को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है.
- ▶ निवारक निरोध के मामलों में, हिरासत के कारणों के बारे में बताना ज़रूरी है.
- ▶ आपातकाल के समय, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ अपवाद हो सकते हैं.

CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना एक संवैधानिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (A) अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार शीघ्र बताने की आवश्यकता है।
- (B) यदि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।
- (C) न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार न बताने से जांच और परीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- (D) यह निर्णय मुख्य रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 से संबंधित है।



साइफलोन 2025 युद्धाभ्यास

UPSC Syllabus Relavanace

- **UPSC Mains Paper 3**





- ▶ भारत और मिस्र के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्सरसाइज साइक्लोन 2025" का तीसरा संस्करण 10 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में शुरू हुआ।
- ▶ यह 14-दिवसीय अभ्यास पेशेवर कौशल साझा करके और रेगिस्तानी वातावरण में विशेष बलों की अंतरसंचालनीयता में सुधार करके भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहता है।





- ▶ अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियान, टोही, छापे और अन्य विशेष मिशन शामिल होंगे, जिनमें स्नाइपिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, टोही, निगरानी और लक्ष्य निर्धारण जैसे विशेष बल कौशल भी शामिल होंगे।
- ▶ भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।



- ▶ मिस्र की टुकड़ी में मिस्र कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र एयरबोर्न प्लाटून शामिल हैं।
- ▶ एक्सरसाइज साइक्लोन द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करने और सामरिक सैन्य अभ्यास के संचालन और चर्चाओं के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ▶ 'डेजर्ट वारियर' एक और द्विपक्षीय अभ्यास है जो दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।

भारत-मिस्र संबंध



भारत-मिस्र संबंध

इतिहास:

- आधुनिक समय में, महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद ज़घलौल का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
- राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को की गई।



भारत-मिस्र संबंध

इतिहास:

- भारत और मिस्र ने 1955 में एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना की।
- वर्ष 2016 में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त वक्तव्य में राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सहभागिता और वैज्ञानिक सहयोग, तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को एक नए युग की नई साझेदारी के आधार के रूप में पहचाना गया था।



भारत-मिस्र संबंध

द्विपक्षीय व्यापार:

- 2022-23 में मिस्र के साथ भारत का व्यापार 6,061 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% कम है।
- इसका लगभग एक तिहाई हिस्सा पेट्रोलियम से संबंधित था।



भारत-मिस्र संबंध

द्विपक्षीय व्यापार:

- भारत मिस्र का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जबकि 2022-23 में मिस्र भारत का 38वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा।
- मिस्र में भारतीय निवेश 50 परियोजनाओं में फैला हुआ है, जिसका कुल मूल्य 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मिस्र ने भारत में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।



भारत-मिस्र संबंध

रक्षा सहयोग:

- 1960 के दशक में दोनों वायु सेनाओं ने लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया तथा 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक भारतीय पायलटों ने अपने मिस्र के समकक्षों को प्रशिक्षित किया।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और मिस्र की वायु सेना दोनों ही फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट उड़ाती हैं।



भारत-मिस्र संबंध

रक्षा सहयोग:

- 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का निर्णय लिया गया है।
- भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास, "अभ्यास साइक्लोन-1" जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में पूरा हुआ।



भारत-मिस्र संबंध

सांस्कृतिक संबंध:

- मौलाना आज़ाद भारतीय संस्कृति केंद्र (MACIC) की स्थापना 1992 में काहिरा में की गई थी। यह केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।



CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: भारत और मिस्र के बीच सैन्य युद्धाभ्यास "साइक्लोन 2025" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह युद्धाभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हो रहा है।
2. इसमें भारत की ओर से गाइड रेजिमेंट भाग ले रही है।
3. इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं।
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं।
- (C) केवल 1 और 3 सही हैं।
- (D) सभी कथन सही हैं।



मणिपुर में संवैधानिक स्थिति विफल और मुख्यमंत्री का इस्तीफा

UPSC Syllabus Relavanace

- **UPSC Mains Paper 2**





मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा

- ▶ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
- ▶ मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उनके निजी सहायक दीपक शिजागुरुमयुम ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की।
- ▶ रविवार शाम को मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया।





इस्तीफे की अहमियत: <<

- ▶ उनके कार्यकाल में मणिपुर में व्यापक हिंसा हुई।
- ▶ विपक्षी दलों ने उन पर हिंसा से निपटने में देरी का आरोप लगाया।



मई 2023: मणिपुर में हिंसा भड़की

- ▶ 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने को कहा।
- ▶ 3 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई।



मई 2023: मणिपुर में हिंसा भड़की

हिंसा के कारण:

- ▶ सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।
- ▶ हजारों लोग बेघर हो गए।
- ▶ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स की तैनाती हुई।



30 मई 2023: अमित शाह का दौरा

- ▶ गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। ✓
- ▶ एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है। ✓
- ▶ 20,000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से निकालकर शिविरों में भेजा गया।
- ▶ अमित शाह ने प्रशासन को सख्ती से हिंसा रोकने के निर्देश दिए।



19 जुलाई 2023: दो महिलाओं का वीडियो वायरल

- ▶ मणिपुर हिंसा की वैश्विक चर्चा।
- ▶ वीडियो में दो कुकी महिलाओं को नग्न परेड करवाया गया।
- ▶ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
- ▶ विपक्ष ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए थे।



जनवरी 2024: भारत जोड़ो न्याय यात्रा

- ▶ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा शुरू की।
- ▶ राहुल गांधी का बयान: "मणिपुर के दर्द को हम समझते हैं, हम राज्य में शांति, प्यार और एकता बहाल करेंगे।"



अप्रैल 2024: लोकसभा चुनाव और पीएम मोदी का बयान

- ▶ लोकसभा चुनाव 2024 के एलान के बाद मणिपुर का मुद्दा उठा।
- ▶ पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोशिशों से हालात में सुधार आया।
- ▶ ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर की हिंसा पर चर्चा हुई।



सितंबर 2024: इम्फाल में फिर भड़की हिंसा

- ▶ 1 सितंबर को हुई हिंसा में एक महिला समेत दो लोगों की मौत।
- ▶ 9 अन्य लोग घायल हुए।
- ▶ मणिपुर पुलिस का दावा: हमलावरों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया।
- ▶ इसके बाद जिरिबाम में हिंसा हुई, जिसमें 4 चरमपंथी और 1 आम नागरिक मारा गया।



नवंबर 2024: एनपीपी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया

- ▶ 11 नवंबर को 10 संदिग्ध चरमपंथी सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए।
- ▶ नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया।
- ▶ एनपीपी का आरोप: "बीरेन सिंह सरकार संकट को हल करने में पूरी तरह विफल।"



दिसंबर 2024: अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल

- ▶ गृह सचिव रहे अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- ▶ उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है।
- ▶ इससे पहले लक्ष्मण आचार्य मणिपुर के कार्यवाहक राज्यपाल थे।



जनवरी 2025: मणिपुर के कांगपोकपी में हिंसा

- ▶ 3 जनवरी को भीड़ ने एसपी ऑफिस पर हमला किया।
- ▶ एसपी मनोज प्रभाकर समेत कई लोग घायल हुए।
- ▶ हिंसा की वजह: 31 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं पर कथित लाठीचार्ज।
- ▶ पुलिस ने कहा: "स्थिति नियंत्रण में, भारी सुरक्षा तैनात।"



निष्कर्ष:

- ▶ मणिपुर में जारी हिंसा के चलते एन बीरेन सिंह का इस्तीफा अहम है।
- ▶ सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई।
- ▶ राजनीतिक अस्थिरता और जातीय तनाव राज्य की प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: मणिपुर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उनके कार्यकाल के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी।
2. मणिपुर की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।
3. सितंबर 2024 में इम्फाल में फिर से हिंसा भड़क उठी थी।

सही उत्तर का चयन करें:

(A) केवल 1 और 2 सही हैं।

(B) केवल 1 और 3 सही हैं।

(C) केवल 2 और 3 सही हैं।

(D) सभी कथन सही हैं।



सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2025

UPSC Syllabus Relavanace

- **UPSC Mains Paper 1**





सूरजकुंड अंतराष्ट्रीय शिल्प मेला

- ▶ आयोजन स्थल: सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा
- ▶ अगला संस्करण: 7 से 23 फरवरी 2025
- ▶ विशेषता: विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला, जो भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है।
- ▶ पर्यटक संख्या: 10 लाख से अधिक, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक शामिल।





सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2025

आयोजन एवं सहयोग

► आयोजक: सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन

सहयोगी मंत्रालय:

► केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय

► कपड़ा मंत्रालय

► संस्कृति मंत्रालय

► विदेश मंत्रालय



सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रस्तुतियाँ

प्रस्तुति स्थल: चौपाल और खुले थिएटर

▶ प्रदर्शन:

- ▶ राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय लोक कलाकारों एवं सांस्कृतिक समूहों की प्रस्तुतियाँ
- ▶ मुख्य चौपाल पर हर शाम विशेष सांस्कृतिक संध्या



सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रस्तुतियाँ

प्रस्तुति स्थल: चौपाल और खुले थिएटर

शिल्प संरक्षण:

- ▶ लुप्त होते पारंपरिक कौशल हेतु विशेष खंड निर्धारित

आकर्षण

▶ खानपान:

- ▶ मल्टी-कुज़ीन फूड कोर्ट, जहां दुनिया भर के व्यंजन उपलब्ध



सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रस्तुतियाँ

प्रस्तुति स्थल: चौपाल और खुले थिएटर

मनोरंजन:

- ▶ साहसिक खेल व आनंद rides के लिए विशेष स्थान
- ▶ रंग-बिरंगी झांकियाँ व ढोल की थाप से भरा माहौल

यात्रा सुझाव :

- ▶ चाहे अकेले हों या परिवार और दोस्तों के साथ, यह एक अवश्य देखने योग्य आयोजन है!

सूरजकुंड



सूरजकुंड

- यह माना जाता है कि इसे 10वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के तोमर राजा सूरज पाल ने बनवाया था। तोमर सूर्य के उपासक थे और इसलिए उन्होंने इसके पश्चिमी तट पर एक सूर्य मंदिर बनवाया था।
- सूरजकुंड एक आदर्श पिकनिक स्थल है, क्योंकि यह दक्षिण दिल्ली से केवल 8 किमी दूर स्थित है। इस मान्यता की पुष्टि करते हुए, सूर्यकुंड के आसपास एक सूर्य मंदिर के खंडहर हैं। परिसर में एक खूबसूरती से सजा हुआ बगीचा और एक कुंड - सिद्ध कुंड शामिल है।



सूरजकुंड

- सबसे महत्वपूर्ण बात, सूरजकुंड ने हर साल यहां आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की मेजबानी के लिए प्रसिद्धि हासिल की है।
- 1 से 15 फरवरी के दौरान मनाया जाने वाला यह मेला भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और लोक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। एक समृद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि के बीच, मेला बहुत मज़ा, मनोरंजन और विशेष खरीदारी के अवसर प्रदान करता है।



सूरजकुंड

- मेला वास्तव में विदेशी, उत्तम और विशिष्ट जातीय वस्तुओं के साथ जीवंत हो उठता है जो नाजुक रूप से कढ़ाई वाले कपड़ों, हाथ से बुने हुए सामान, टेराकोटा कलाकृतियों, आभूषणों, धातु और बेंत के बर्तनों से लेकर हैं। फूड कोर्ट में तरह-तरह के मुंह में पानी लाने वाले भारतीय व्यंजनों को न भूलें।
- इसके अलावा, चौपाल और नाट्यशाला लोक नृत्यों और संगीत की शामों के साथ स्पंदित होते हैं जो पूरे अनुभव में रंगों का दंगा और लय की खुशी जोड़ते हैं।



सूरजकुंड

- हर साल भारत के सभी कोनों से राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता शिल्पकार मेले में भाग लेते हैं। वर्ष 2013 में 27वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला देखा गया।
- मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो देश की कुछ बेहतरीन हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को उजागर करता है।



सूरजकुंड

- फरवरी के पहले पखवाड़े में ग्रामीण भारत दक्षिण दिल्ली से लगभग 8 किमी दूर सूरजकुंड मेला गांव में प्रशंसा की गर्मी में सराबोर होता है। मेला विरासत, संस्कृति और कला रूपों का भी जश्न मनाता है। हर साल एक अलग थीम राज्य चुना जाता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है।



CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है।
2. इसका आयोजन केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. इस मेले में केवल भारतीय शिल्पकारों को भाग लेने की अनुमति होती है।

सही उत्तर का चयन करें:

- (A) केवल 1 सही है।
- (B) केवल 1 और 2 सही हैं।
- (C) केवल 2 और 3 सही हैं।
- (D) सभी कथन सही हैं।



Thank You

